राजिन्दर उर्फ राजू

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(2003 की आपराधिक अपील संख्या 670)

7 जुलाई, 2009

[वी. एस. सिरपुरकर और आर. एम. लोधा, जे. जे.]

दंड संहिता 1860-एसएस 366 और 376 के तहत दोष सिद्धी- चुनौती, इस आधार पर की आरोपी ने अभियोक्त्री की सहमति से यौन संबंध बनाये। अभिनिर्धारित तथ्यों पर, तर्क संगत नहीं-अभियोक्त्री ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्त ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाये- विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने उसके साक्ष्य को स्वीकार किया-कोई अलग दृष्टिकोण लेने का कोई यथोचित कारण नहीं था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियोक्त्री के शरीर पर चोटों की अनुपस्थिति होना इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है कि उसने अभियुक्त के साथ यौन संबंध के लिए सहमति दी। युवा लड़की अभियुक्त की वासना के कारण पीड़िता बनी, जो उसकी उम्र से दो गुनी उम्र का था और जिसने उसे उसकी इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। साक्ष्य-यौन उत्पीड़न की शिकार-महिलाओ के खिलाफ अपराध-बलात्कार।

अभियोक्त्री ने आरोप लगाया था कि उसे अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा दुर्व्यपदेशित किया गया कि वह उसे अपने चचेरे भाई (एक डाक्टर) को दिखायेगा, क्योंकि वह गले के दर्द से पीड़ित थी और वह उसके साथ चली गयी। लेकिन आरोपी उसे दूसरी जगहों पर ले गया और जब अंधेरा हो गया तब वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाये। सुसंगत समय में अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष थी। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को

भारतीय दंड संहिता की धारा 366 एवं धारा 376 के तहत दोषी मानते हुए उसे साथ साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय द्वारा उस दोषसिद्धी और सजा की पुष्टि की गयी।

इस न्यायालय में अपील में दोष सिद्धी को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि यौन संबंध अभियोक्त्री की सहमति से बनाये गये थे।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि,

1.1 अभियोक्त्री ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाये। हालांकि अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा कि आरोपी ने उसे कटार दिखाकर धमकी दी थी, जब उसने उसके साथ जाने से इंकार कर दिया था और इस पहलू को उसने अपने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताया था लेकिन यह खंडन मात्र उसकी साक्ष्य को अविश्वास योग्य नहीं बनाता है। अतः अलग दृष्टिकोण लिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। (पैरा 9 और 10) (255-ए, सी, डी)

1.2 प्रकरण की परिस्थितियां न ही मामले को व्यक्तिगत रूप से न ही सामूहिक रूप से किसी भी ऐसे प्रशंसनीय अनुमान की ओर ले जाता है कि अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध अभियुकत द्वारा उसकी मौन सहमति से बनाये गये थे। (पैरा-11) (255-ई)

1.3 भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, यौन आक्रामक्ता का शिकार होने वाली महिला किसी को झूंठे तरीके से फंसाने की अपेक्षा मौन रहने को

प्राथमिकता देती है। बलात्कार का कोई भी बयान एक महिला के लिए एक बेहद अपमानजनक अनुभव होता है और जब तक वह यौन अपराध की शिकार नहीं होती, तब तक वह वास्तव में किसी को अपराध का दोष नहीं देती। पीड़िता के साक्ष्य की विवेचना करते समय न्यायालयों को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी आत्मसम्मान वाली महिला बलात्कार का झूंठा आरोप लगाकर अपना सम्मान दाव पर नहीं लगायेगी और इसलिए आमतौर पर उसकी गवाही की पुष्टि की तलाश बिल्कुल अनावश्यक है। लेकिन अभियोजन मामलें में अत्यधिक असंभाव्यता के लिए, यौन अपराध के मामलें में दोष सिद्धी एक मात्र पीड़िता के अभिसाक्ष्य के आधार पर हो सकती है।

ए. अभियोक्त्री की गवाही। (पैरा 21) (262-जी-एच 263-ए)

1.4 बलात्कार के प्रत्येक मामले में पुष्टिकारक साक्ष्य न्यायिक साख का आज्ञापक घटक नहीं है और न ही पीड़िता के निजी अंगों पर चोटों की अनुपस्थिति को सहमति के साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, परिस्थितियां अभियोक्त्री के साक्ष्य को खारिज करने के लिए न तो पर्याप्त है न ही न्यायोचित है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभियोक्त्री के साक्ष्य के बारे में कोई संदेह/अविश्वास उत्पन्न करता हो। इस तरह के एक मामले में, जहां अभियोक्त्री को अभियुक्त द्वारा यह दुर्व्यपदेशित किया गया था कि वह उसे अपने चचेरे भाई (एक डाक्टर) को दिखायेगा क्योंकि वह कुछ गले के दर्द

से पीड़ित थी और वह उसके साथ चली गयी। लेकिन आरोपी उसे दूसरी जगहों पर ले गया और जब अंधेरा हो गया, उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाये, अभियोक्त्री से कोई भी प्रतिरोध करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसकी जान को खतरा था। तथ्यों और परिस्थितियों में अभियोक्त्री के शरीर पर चोटो की अनुपस्थिति से यह निष्कर्ष नहीं निकलता की उसने आरोपी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी। युवा लड़की आरोपी की वासना का शिकार हो गयी जो उसकी उम्र से दो गुनी से अधिक उम्र का था और उसने उसकी इच्छा के विरूद्ध संभोग करने के लिए हार मान ली थी। कुल मिलाकर उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय जिसमें धारा 366 और 376 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियुक्त को दोषी टहराया गया था, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गयी थी, में कोई विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलार्थी को दी गयी सजा में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। (पैरा 21 और 22) (263-बी-एफ)

पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य, (1996) 2 एस. सी. सी. 384 और राजस्थान राज्य बनाम। एन. के. (2000) 5 एस. सी. सी. 30, पर भरोसा किया।

प्रताप मिश्रा और ओआरएस। बनाम उड़ीसा राज्य (1977) 3 एससीसी 41: सदाशिव रामराव हदबे बनाम महाराष्ट्र राज्य और एन. आर. (2006) 10 एस. सी. सी. 92 और नारायण उर्फ नारन बनाम राज्य

राजस्थान (2007) 6 एस. सी. सी. 465 और राधु बनाम राज्य मध्य प्रदेश (2007) 12 एससीसी 57, विशिष्ट।

मामला कानून संदर्भः

(1996) 2 एस. सी. सी. 384 भरोसा करें पैरा 1

(1977) 3 एससीसी 41 प्रतिष्ठित पैरा 12

(2006) 10 एस. सी. सी 92 प्रतिष्ठित पैरा 12

(2007) 6 एस. सी. सी. 465 प्रतिष्ठित पैरा 12

(2007) 12 एससीसी 57 प्रतिष्ठित पैरा 12

(2000) 5 एससीसी 30 भरोसा करें पैरा 19

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील 2003 का सं. 670। उच्च न्यायालय के 01.11.2002 दिनांकित निर्णय और आदेश से शिमला में हिमाचल प्रदेश की अदालत ने आपराधिक अपील सं। 484 2002 से।

अपीलार्थियों की ओर से अशोक माथुर और अंशुल नारायण।

प्रत्यर्थी की ओर से नरेश के शर्मा।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस आर.एम. लोढ़ा द्वारा पारित किया गया

1. बलात्कारी न केवल पीड़िता की निजता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक क्षिति पहुंचाता है। बलात्कार केवल हमला नहीं

है - यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। हत्यारा अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है। बलात्कारी असहाय नारी की आत्मा को अपमानित करता है। [पंजाब राज्य बनाम गुरमित सिंह और अन्य 1]

2. सबसे पहले, अभियोजन मामले का एक संक्षिप्त संदर्भ।

अभियोक्त्री (नाम हमने छुपाया है), लगभग 18 वर्ष की एक युवा लड़की, ग्राम कोठी, जिला बिलासपुर, (हिमाचल प्रदेश) में अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। आरोपी राजिंदर उर्फ राजू, निवासी ग्राम डूहक, जिला बिलासपुर ने पीड़िता के निवास के पास (1996) 2 एससीसी 384 ग्राम कोठी में जीआई पाइपलाइन बिछाने का ठेका लिया था। उस संबंध में, वह अपना सामान अभियोक्त्री के माता-पिता के घर में संग्रहीत करता था। 16 जनवरी 1996 को अभियोक्त्री को गले में कुछ दर्द हुआ। जब आरोपी पीड़िता के घर आया और उसे पता चला कि पीड़िता के गले में दर्द हो रहा है, तो उसने पीड़िता की मां को सुझाव दिया कि घुमारवीं में उसका चचेरा भाई एक डॉक्टर है और अगर अनुमति हो, तो वह पीड़िता को उसके भाई को दिखा सकता है। अभियोक्त्री की माँ सहमत हो गई। आरोपी पीड़िता को दोपहर करीब 3.00 बजे अपने स्कूटर पर ले गया। पीड़िता को घुमारवीं ले जाने के बजाय, वह उसे यह कहते हुए जबलू ले गया कि उसे अपने किरायेदारों से किराया लेना है। जबलू से आरोपी पीड़िता को बर्थिन ले गया। आरोपी अभियोक्त्री के साथ लगभग 8.00 - 8.30 बजे बरथीन

पहुंचा। बर्थिन में, आरोपी ने कुछ मिठाइयाँ खरीदीं और पीड़िता से कहा कि वह उसे अपने घर ले जाएगा क्योंकि अंधेरा है। आरोपी उसे अपने घर ले जाने के बजाय स्कूटर से किसी कच्ची सड़क पर ले गया और उसे स्कूटर से नीचे उतार दिया। अपना पट्टू जमीन पर फैलाकर और अभियोक्ता का मुंह बंद करके उसे लिटा दिया; उसकी सलवार खोल दी और उसके साथ जबरन दुराचार किया। इसके बाद आरोपी अपना पट्टू और टॉर्च छोड़कर चला गया। आरोपी के जाने के बाद, पीड़िता को सड़क के नीचे एक घर से कुछ रोशनी दिखाई दी। वह उस घर तक चली गई और वहां रहने वाली महिला श्रीमती बिमला देवी (पीडब्लू-2) को घटना के बारे में बताया गया। अभियोक्त्री रात भर पीडब्लू-2 के घर में रुकी। पीडब्लू-2 ने पूरी घटना अपने पति (पीडब्लू-3) को बताई। सुबह पीडब्लू-3 ने ग्रामीणों को बुलाया; अभियोक्त्री का बयान ग्रामीणों में से एक रूप सिंह (पीडब्लू-4) द्वारा दर्ज किया गया था। इसके बाद घुमारवीं पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। अभियोक्त्री एवं अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। जांच अधिकारी ने पीड़िता के परिधान को अपने कब्जे में ले लिया और उसे आरोपी की योनि स्लाइड और अंडरवियर के साथ रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि पीड़िता अनुसूचित जाति की थी। जांच पूरी होने के बाद, आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 और 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989 की धारा 3 (XII) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

3. सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने उपरोक्त अपराध के लिए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय किया। अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री (पीडब्लू-1), पूछताछ की। बिमला देवी (पीडब्लू-2), सुरम सिंह (पीडब्लू-3), रूप सिंह (पीडब्लू-4), श्रीमती। शीला देवी (पीडब्लू-5), प्रेम सिंह (पीडब्लू-6), डॉ. एससी कौशल (पीडब्लू-7), पुलिस अधिकारी (पीडब्लू 8 से 12) और डॉ. सविता मेहता (पीडब्लू-13)।

4. सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान दर्ज किया गया। उन्होंने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और बचाव पक्ष स्थापित किया कि उनके खिलाफ मामला पीडब्लू-2, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-6 के आदेश पर तैयार किया गया है। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में यह भी कहा कि पीड़िता की मां (पीडब्लू-5) ने रुपये की लकड़ी ली थी। 5,000/- और जब उसने बकाया राशि के भुगतान की मांग की, तो पीडब्लू-5 ने रुपये की मांग की। उससे 50,000/- रुपये मांगे और कहा कि उपरोक्त राशि के भुगतान के बाद ही वह उसके खिलाफ मामला खत्म कर देगी।

5. सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989 की धारा 3 (बारहवीं) के तहत आरोप से बरी कर दिया, लेकिन आरोपी को धारा 366 और 376 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया तथा अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास और

10,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई तथा जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम करने पर धारा 376 भारतीय दंड संहिता के ही गंभीर अपराध की सजा सुनाई गई।

6. अभियुक्त ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। अतः वर्तमान में यह विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की गई है।

7. अभियुक्त के विद्वान वकील श्री अशोक मेहता ने हमारे समक्ष इस बात पर विवाद नहीं किया कि अभियुक्त ने घटना के समय और स्थान पर पीड़िता के साथ संभोग किया था। उनके तर्क का जोर यह था कि आरोपी ने कथित कृत्य जबरन नहीं किया; बल्कि ऐसा कृत्य अभियुक्त द्वारा पीड़िता की सहमति और स्वतंत्र इच्छा से किया गया था। उपरोक्त तर्क पर उच्च न्यायालय के समक्ष भी बहस की गई और निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया, अर्थात् प्रासंगिक समय पर अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष थी और इस प्रकार वह यौन संबंध के लिए सहमति देने में सक्षम थी; अभियोक्त्री के शरीर पर चोट/चोट का अभाव उसकी सहमति का सूचक है जो इस तथ्य से और भी मजबूत होता है कि कहा जाता है कि यौन संबंध का कृत्य आरोपी द्वारा जमीन पर पट्टा रखने के बाद किया गया था और अभियोक्त्री प्रारंभ से ही स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ गया; और यह कि आरोपी द्वारा अभियोक्त्री को खंजर दिखाकर धमकाने का पहलू

स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि इसका प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है।

8. चूंकि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाने का कृत्य स्वीकार किया गया है, इसलिए हम चिकित्सकीय साक्ष्य पर अधिक विस्तार से विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इतना कहना पर्याप्त है कि डॉ. सविता (पीडब्लू-13) ने 18 जनवरी 1996 को अभियोक्त्री की जांच की। उस समय उसके कपड़े खून से सने हुए पाए गए। पीडब्लू-13 की राय है कि जांच के 48 घंटों के भीतर पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाया गया था। उन्होंने शुक्राणु की उपस्थिति का पता लगाने के लिए योनि परीक्षण भी किया। पीडब्लू-13 के अनुसार, अभियोक्त्री को संभोग करने की आदत नहीं थी और, उसकी राय में, अभियोक्त्री पर पहली बार यौन उत्पीड़न किया गया था इससे पहले कि वह उसकी जांच करती। वह यह बताने की स्थिति में नहीं थी कि यौन कृत्य पीड़िता की सहमति से किया गया था या यह जबरन किया गया था। इन परिस्थितियों में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी ने घटना की तारीख और स्थान पर पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए थे। बहस का मुख्य बिंदु यह है कि क्या ऐसा कृत्य अभियोजक की सहमति से किया गया था या नहीं।

9. पीड़िता ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी ने उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। उसने गवाही दी:

"जाते समय, आरोपी ने सड़क पर एक सुनसान जगह पर स्कूटर रोका और उसके बाद उसने मुझे सड़क से कुछ दूरी पर सुनसान जगह मेरी बांह से पकड़कर मुझे खींच लिया और मेरा मुंह बंद कर दिया और जमीन पर 'पट्टू' रखने के बाद उसने मेरा सलवार खोल दिया और मेरे साथ यौन संबंध बनाए। मुझे अपने प्राइवेट पार्ट में दर्द महसूस हुआ और खून निकलने लगा।'

10. यह सच है कि अपनी जिरह में उसने कहा कि जबलू के साथ जाने से इनकार करने पर आरोपी ने उसे खंजर से धमकाया था और यह पहलू न तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उसके बयान में बताया गया था और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेकिन क्या यह विरोधाभास उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है? हम ऐसा नहीं सोचते। विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी उसकी गवाही को स्वीकार कर लिया है। भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई उचित कारण नहीं मिलता।

11. विद्वान वकील द्वारा जिन परिस्थितियों को इंगित किया गया है, वे न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही सामूहिक रूप से किसी भी प्रशंसनीय निष्कर्ष पर ले जाती हैं कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ यौन संबंध उसकी मौन सहमति से किया गया था।

12. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया, अर्थात्, (1) प्रताप मिश्रा और अन्य। बनाम उड़ीसा राज्य 2, (2) सदाशिव रामराव हदबे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 3,(3) नारायण उर्फ नाराण बनाम राजस्थान राज्य 4 और (4) राधू बनाम मध्य प्रदेश राज्य 5 ।

13. यह कि अभियुक्त अपनी दलील से बंधा नहीं है और अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा की गई स्वीकारोक्ति या मामले में सिद्ध परिस्थितियों के आधार पर भी बिना किसी संदेह के अपना बचाव साबित करना उसके लिए खुला है। हालाँकि, जहाँ तक प्रताप मिश्रा के मामले में फैसले का सवाल है, इस अदालत ने सबूतों पर विचार करते हुए कहा कि अपीलकर्ताओं ने पीड़िता के साथ उसकी मौन सहमति और उसके पति की मिलीभगत से यौन संबंध बनाए थे। इस न्यायालय ने (1977) 3 एससीसी 41 (2006) 10 एससीसी 92 (2007) 6 एससीसी 465 (2007) 12 एससीसी 57 माना कि बलात्कार के आरोप को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। यहां तक कि उसमें मौजूद चिकित्सीय साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते थे। हमें डर है कि प्रताप मिश्रा मामले में इस अदालत का फैसला अपने ही तथ्यों से उलट है और इससे अपीलकर्ता को कोई मदद नहीं मिलेगी।

14. सदाशिव रामराव हदबे मामले में, इस न्यायालय ने यह दोहराते हुए कि बलात्कार के मामले में, अभियुक्त को अभियोक्त्री की एकमात्र

गवाही पर दोषी ठहराया जा सकता है यदि यह न्यायालय के मन में विश्वास पैदा करने में सक्षम है, चेतावनी का एक शब्द रखा कि जब पूरा मामला असंभव और घटित होने की संभावना न हो तो अदालत को गवाही स्वीकार करते समय बेहद सावधान रहना चाहिए। यही कहा गया है:

> "9. यह सच है कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त को अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर दोषी ठहराया जा सकता है, यदि यह अदालत के मन में विश्वास पैदा करने में सक्षम है। यदि अभियोजक द्वारा दिया गया बयान किसी भी चिकित्सा द्वारा समर्थित नहीं है सबूत या आसपास की पूरी परिस्थितियाँ अत्यधिक असंभाव्य हैं और अभियोक्त्री द्वारा स्थापित मामले को झुठलाती हैं, अदालत अभियोक्त्री के अकेले साक्ष्य पर कार्रवाई नहीं करेगी। अदालतें अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही को स्वीकार करने में बेहद सावधान रहेंगी जब पूरा मामला यह असंभव है और ऐसा होने की संभावना नहीं है।"

15. यह ध्यान देने योग्य है कि सदाशिव रामराव हदबे मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि अभियोजन साक्ष्य कई विरोधाभासों से ग्रस्त थे और पूरी घटना अत्यधिक असंभव प्रतीत होती थी। यह सच है कि सदाशिव रामराव हदबे मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि पीड़िता के शरीर पर चोटों की अनुपस्थिति

अभियोजन पक्ष के संस्करण को असंभाव्य बनाती है, लेकिन उपरोक्त टिप्पणी को यौन संबंध स्थापित करने के लिए सबूतों की अपर्याप्तता के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। इस न्यायालय ने यही कहा:

"10. वर्तमान मामले में क्लिनिक में बहुत सारे लोग थे और यह बेहद असंभव है कि अपीलकर्ता ने जांच के लिए आए मरीज पर यौन हमला किया होगा, जब पास में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यह है यह भी अत्यधिक असंभव है कि पीड़िता कोई शोर नहीं कर सकती थी या डॉक्टर द्वारा हमला किए बिना कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि वह सामान्य शारीरिक गठन वाली 20 साल की एक सक्षम व्यक्ति थी।

सदाशिव रामराव हदबे मामले में फैसले से आरोपियों को कोई मदद नहीं मिलती है.

16. नारायण के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह माना गया कि अभियोक्ता का साक्ष्य विरोधाभासों से भरा था। एफआईआर में लगाए गए आरोपों की पृष्ठभूमि में कि आरोपी ने पीड़िता के साथ तीन बार बलात्कार किया, इस अदालत ने माना कि उसके शरीर या निजी अंगों पर चोटों के अभाव में जबरन यौन संबंध के अभियोजन मामले को खारिज कर दिया गया। इतना कहना काफ़ी होगा कि नारायण का मामला अपने ही तथ्यों से पलट गया। जहां तक कानूनी स्थिति का सवाल है, इस न्यायालय ने

दोहराया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ही आरोपी की दोषसिद्धि को कायम रख सकते हैं।

17. राधू के इस न्यायालय ने इस मामले पर इस प्रकार विचार किया:

> "12. डॉ. वंदना (पीडब्लू 8) ने कहा कि सुमनबाई की जांच करने पर, उन्होंने पाया कि उनका मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ था और जघन बाल विकसित नहीं हुए थे, और उनका हाइमन टूट गया था, लेकिन टूटना पुराना था। उन्होंने कहा कि वहाँ थे उसके निजी अंगों पर कोई चोट नहीं थी और वह इस बारे में कोई राय नहीं दे सकी कि क्या कोई बलात्कार किया गया था। ये जांच रिपोर्ट (एक्सटेंशन पी-8) में भी दर्ज किए गए थे। हालाँकि, उसने बायीं कोहनी पर खरोंच का जिक्र किया था और सुमनबाई की बांह पर एक छोटी सी खरोंच और दाहिने पैर पर एक खरोंच है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जांच के लिए दो योनि स्वैब तैयार किए और सुमनबाई के पेटीकोट के साथ पुलिस कांस्टेबल को सौंप दिया, ताकि उन्हें जांच के लिए भेजा जा सके। लेकिन योनि स्वैब और पेटीकोट की जांच के परिणामों के बारे में कोई सबूत नहीं दिया गया है। इस

प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य यौन संबंध या बलात्कार के मामले की पुष्टि नहीं करते हैं।

13. इस प्रकार हमारे पास अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही और चिकित्सीय साक्ष्य बचे हैं कि सुमनबाई की बायीं कोहनी पर खरोंच थी, उसकी बांह पर खरोंच थी और उसके पैर पर चोट थी। लेकिन चोटों के ये निशान, अपने आप में, बलात्कार, गलत कारावास या चोट को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, अगर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य भरोसेमंद नहीं पाए जाते हैं और कोई पुष्टि नहीं होती है।

14. ललिताबाई का कहना है कि जब सुमनबाई वापस नहीं लौटी तो उसने ग्यारसीबाई से पूछताछ की. सुमनबाई का यह भी कहना है कि वह अक्सर ग्यारसीबाई के घर जाया करती थी. वह कहती है कि राधू के माता-पिता उसकी मां के काका और बाबा हैं और राधू उसका मामा था। परिवार आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और उनके संबंध सौहार्दपूर्ण थे। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष का मामला कि ग्यारसीबाई ने अपने बेटे राधू को सुमनबाई के साथ बलात्कार करने के लिए उकसाने के लिए सुमनबाई को अपने घर बुलाया होगा और जब बलात्कार किया गया था तब पूरी रात ग्यारसीबाई छोटे से घर में मौजूद थी, यह

साक्ष्यों और परिस्थितियों के आलोक में अत्यधिक असंभव प्रतीत होता है।

15. प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि दिनेश नामक व्यक्ति को ललिताबाई ने अपने पति को लाने के लिए भेजा था। ललिताबाई और मांगीलाल ने कहा कि वे दिनेश नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। सुमनबाई ने अपने साक्ष्य में कहा कि 29-1-1991 को, क्योंकि उसके पिता बाहर थे, उसके जीजा उसके पिता को वापस लाने गए, उसके जीजा का नाम रमेश था, लेकिन SHO ने गलत लिखा उसका नाम "दिनेश" है। लेकिन किसी और ने ऐसी गलती का जिक्र नहीं किया. न तो रमेश और न ही दिनेश की जांच की गई।

16. अभियोजक के साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ने पर, विसंगतियों से भरा हुआ है और विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। साक्ष्यों में कमियाँ, साक्ष्यों में कई विसंगतियाँ और अन्य परिस्थितियाँ इस बात को अत्यधिक असंभव बनाती हैं कि ऐसी कोई घटना कभी घटित हुई हो। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बचाव पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़िता के पिता मांगीलाल, राधू के पिता नाथू के ऋणी थे और परिणामस्वरूप, आरोपी को

गलत फंसाने के बचाव को खारिज कर दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष की ओर से दिए गए सुझाव को पीड़िता की मां और पिता द्वारा खारिज किए जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि सुमनबाई के पिता मांगीलाल, राधू के पिता नाथू के ऋणी थे और क्योंकि नाथू पैसे की मांग कर रहा था, इसलिए उन्होंने कर्ज चुकाने से बचने के लिए बलात्कार का झूठा आरोप लगाया था । . यह तथ्य कि बचाव पक्ष मांगीलाल की ऋणग्रस्तता या झूठे आरोप लगाने के किसी उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा, इसकी अधिक प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि सबूत बिल्कुल भी अपराध का निष्कर्ष निकालने की गारंटी नहीं देते हैं, और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपराध का निष्कर्ष निकालने में गलती की है।"

18. फिर से राधू के मामले में, अभियोक्ता के साक्ष्य विसंगतियों से भरे हुए और विश्वसनीयता के योग्य नहीं पाए गए। चिकित्सकीय साक्ष्य भी यौन संबंध या बलात्कार के मामले की पुष्टि नहीं करते। राधू मामले में इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को इस प्रकार दोहराया:

"6. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि बलात्कार के मामले में अपराध की खोज, पीड़िता के असंपुष्ट साक्ष्य पर आधारित हो सकती है। अपराध की प्रकृति के कारण सीधे पुष्टि करने वाले साक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। अभियोजक का साक्ष्य होना चाहिए मामूली विसंगतियों और विरोधाभासों के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। यदि बलात्कार की पीड़िता शपथ लेकर कहती है कि उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए थे, तो उसका बयान आम तौर पर स्वीकार किया जाएगा, भले ही वह अपुष्ट हो, जब तक कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के लिए ऐसा करने की आवश्यकता न हो। एक अनुमान कि सहमति थी या पूरी घटना असंभव या काल्पनिक थी। अगर सहमति है, तो भी कृत्य "बलात्कार" होगा, अगर लड़की 16 वर्ष से कम उम्र की है। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि सहमति का अभाव पीड़िता के निजी अंगों पर चोटें न तो बलात्कार के मामले को झूठा साबित करेंगी और न ही इसे सहमति का सबूत माना जाएगा।"

इस प्रकार, राधू में यह माना गया है कि पीड़ित के निजी अंगों पर चोटों की अनुपस्थिति को सहमति के सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है।

19. राजस्थान राज्य बनाम एनके में । 6, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"19. भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में परिभाषित बलात्कार के अपराध के लिए , संभोग महिला की इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना होना चाहिए। तीसरे से छठे खंड के अंतर्गत आने वाली कुछ परिस्थितियों में सहमति महत्वहीन है। आखिरी बात तब होती है जब महिला की उम्र 16 वर्ष से कम हो। इन प्रावधानों के आधार पर, आमतौर पर बलात्कार के आरोपी की ओर से एक तर्क दिया जाता है कि जहां अभियोजक की उम्र 16 वर्ष से कम नहीं है, वहां सहमति की कमी के सबूत का अभाव है। हमले को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के दायरे से बाहर कर देता है। यदि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम है तो निश्चित रूप से सहमति कोई बचाव नहीं है। यदि वह 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र की है, तो उसकी सहमति बचाव नहीं हो सकती है । मान लिया गया; सहमति के बारे में एक निष्कर्ष केवल सबूतों या मामले की संभावनाओं के आधार पर ही निकाला जा सकता है। बलात्कार की पीड़िता ने शपथ लेकर कहा है कि उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए थे या यह कार्य उसकी सहमति के बिना किया

गया था, इस पर विश्वास किया जाना चाहिए और किसी भी अन्य गवाही की तरह स्वीकार किया जाता है जब तक कि उसकी सहमति के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री उपलब्ध न हो अन्यथा अभियोक्ता की गवाही ऐसी है जो स्वाभाविक रूप से असंभव होगी।"

20. इस न्यायालय ने, गुरमित सिंह1 के मामले में, यौन उत्पीड़न की पीड़िता के साक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

"अदालतों को सबूतों का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि बलात्कार के मामले में, कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने सम्मान के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए अदालत में आगे नहीं आएगी, जैसे कि बलात्कार के आयोग में शामिल है उस पर।

यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, कथित विचार जिनका अभियोजन मामले की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है या यहां तक कि अभियोक्त्री के बयान में विसंगतियां भी नहीं होनी चाहिए, जब तक कि विसंगतियां ऐसी न हों जो घातक प्रकृति की हों, उन्हें अन्यथा बाहर फेंकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विश्वसनीय अभियोजन मामला. महिलाओं की अंतर्निहित शर्मीलेपन और

यौन आक्रामकता के आक्रोश को छिपाने की प्रवृत्ति (2000) 5 एससीसी 30 हैं।

ऐसे कारक जिन्हें अदालतों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक कोई ठोस कारण न हो जिसके लिए उसके बयान की पुष्टि की आवश्यकता हो, अदालतों को किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अकेले यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आत्मविश्वास जगाता है और विश्वसनीय पाया जाता है। ऐसे मामलों में, एक नियम के रूप में, उसके बयान पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि की मांग करना जले पर नमक छिड़कने के समान है। बलात्कार या यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की या महिला की गवाही को संदेह, अविश्वास या शंका की दृष्टि से क्यों देखा जाना चाहिए? अदालत अभियोक्त्री के साक्ष्य की सराहना करते हुए अपनी न्यायिक अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासन की तलाश कर सकती है, क्योंकि वह एक गवाह है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखती है, लेकिन जोर देने के लिए कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी आरोपी को दोषी

ठहराने के लिए उसके बयान की पुष्टि की जाती है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिला का साक्ष्य लगभग एक घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर है और कुछ हद तक उससे भी अधिक विश्वसनीय है। जिस तरह एक गवाह को घटना में कुछ चोट लगी है, जो खुद को पहुंचाई हुई नहीं पाई गई है, उसे इस अर्थ में एक अच्छा गवाह माना जाता है कि वह वास्तविक अपराधी को बचाने की कम से कम संभावना रखता है, पीड़ित का सबूत एक यौन अपराध को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, इसके बावजूद पुष्टि का अभाव होता है। बलात्कार के हर मामले में पुष्टिकारक साक्ष्य न्यायिक साख का अनिवार्य घटक नहीं है। अभियोजक की गवाही पर न्यायिक निर्भरता के लिए एक शर्त के रूप में संपुष्टि कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला या लड़की अपराध में भागीदार नहीं है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की वासना का शिकार है और उसे एक निश्चित मात्रा में संदेह के साथ उसके साक्ष्य का परीक्षण करना अनुचित और अवांछनीय है। अगर वह एक सहयोगी होती. यथार्थवादी विविधता के साथ तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, न कि मृत एकरूपता के

साथ, ऐसा न हो कि कानून के शासन के आकार में उस प्रकार की कठोरता प्रशंसात्मक अत्याचार के एक नए रूप के माध्यम से पेश की जाए जो न्याय को हताहत बना दे। अदालतें किसी जीवाश्म सूत्र पर टिकी नहीं रह सकती हैं और पुष्टि पर जोर नहीं दे सकती हैं, भले ही समग्र रूप से देखा जाए तो यौन अपराध की पीड़िता द्वारा बोला गया मामला न्यायिक दिमाग पर संभावित प्रभाव डालता है।"

21. भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, एक महिला - यौन आक्रामकता की शिकार - किसी को झूठा फंसाने के बजाय चुपचाप सहना पसंद करेगी। बलात्कार का कोई भी बयान एक महिला के लिए बेहद अपमानजनक अनुभव होता है और जब तक वह यौन अपराध का शिकार नहीं होती, तब तक वह असली अपराधी के अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहराती। पीड़िता के साक्ष्य की सराहना करते समय, न्यायालयों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्वाभिमानी महिला उस पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर अपना सम्मान दांव पर नहीं लगाएगी और इसलिए, आमतौर पर उसकी गवाही की पुष्टि की तलाश अनावश्यक है और अयोग्य के लिए। लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले में अत्यधिक असंभाव्यता के लिए, यौन अपराध के मामले में दोषसिद्धि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है। यह ठीक ही कहा गया है कि बलात्कार के हर मामले में पुष्टिकारक साक्ष्य न्यायिक साख का अनिवार्य घटक नहीं है और

न ही पीड़िता के निजी अंगों पर चोटों की अनुपस्थिति को सहमति के साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, विद्वान वकील द्वारा उल्लिखित और बताई गई परिस्थितियां न तो पर्याप्त हैं और न ही वे अभियोजक के साक्ष्य को खारिज करने को उचित ठहराती हैं। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभियोजक के साक्ष्य के बारे में कोई संदेह/अविश्वास या संदेह पैदा करता हो। इस तरह के एक मामले में, जहां अभियुक्त ने पीड़िता को दुर्व्यपदेशित किया था कि वह उसे अपने चचेरे भाई (एक डॉक्टर) को दिखाएगा क्योंकि वह गले में कुछ दर्द से पीड़ित थी और वह उसके साथ गई थी लेकिन अभियुक्त उसे अन्य स्थानों पर ले गया और जब अंधेरा हो गया, उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ दुराचार किया, अभियोक्ता से कोई प्रतिरोध करने की अपेक्षा नहीं की गई, अन्यथा उसकी जान खतरे में पड़ जाती। तथ्यों और परिस्थितियों में, पीड़िता के शरीर पर चोटों की अनुपस्थिति से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उसने आरोपी के साथ संभोग के लिए सहमति दी थी। युवा लड़की अपने से दोगुने से भी अधिक उम्र के आरोपी की हवस का शिकार बन गई और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हो गई।

22. कुल मिलाकर, हम पाते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 और 376 के तहत अभियुक्तों को दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय किसी भी कानूनी दोष से ग्रस्त नहीं है। अपीलकर्ता को दी गई सजा में इस

न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपील जिसमें कोई गुणावगुण नहीं है, असफल है और खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपने जमानत मुचलकों पर आत्मसमर्पण करेगा और उसे दी गई सजा भुगतने के लिए अभिरक्षा में लिया जायेगा।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निधि शर्मा-प्रथम (आर.जे.एस.), अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, टोंक राजस्थान द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।